



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032020-217569
CG-DL-E-07032020-217569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 2020/फाल्गुन 14, 1941

No. 62]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 2020/PHALGUNA 14, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

मामला सं. (एसजी)01/2020

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

विषय: भारत में "सौरसेल, चाहे वे माड्यूलों अथवा पैनलों में असेम्बल किए गए हों अथवा नहीं" के आयातों पर लगाए गए रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने के लिए समीक्षा जांच की शुरुआत।

- फा. सं. 22/1/2020-डीजीटीआर.—भारतीय सौर निर्माताओं के संघ(आईएसएमए) के माध्यम से (i) मैसर्स मुन्द्रा सोलर पी वी लिमिटेड, एक विशिष्ट आर्थिक जोन में एक यूनिट("एसईजैड यूनिट"), (ii) मैसर्स जूपिटर सोलर पावर लिमिटेड, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में एक यूनिट ("डीटीए यूनिट"), और (iii) मैसर्स जूपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, एक डीटीए यूनिट द्वारा भारत में "सौरसेल, चाहे वे माड्यूलों अथवा पैनलों में असेम्बल किए गए हों अथवा नहीं" (जिन्हें यहां "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की मांग करते हुए सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे यहां "नियम" भी कहा गया है) के नियम 18 के तहत रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा करने और उसका विस्तार करने के लिए एक आवेदन दायर किया है

ताकि घरेलू उत्पादकों को समान और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं (विचाराधीन उत्पाद) को ऐसे आयातों की वृद्धि के कारण गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका से बचाया जा सके।

2. वर्तमान आवेदन के तहत रक्षोपाय नियमावली के नियम 16 (2) के प्रथम परन्तुक के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे यहां “अधिनियम” भी कहा गया है) की धारा 8 बी की उपधारा 4 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में आगे की चार वर्षों की अवधि के लिए उक्त शुल्क को जारी रखने की मांग की गई है।

पृष्ठभूमि:

3. पांच भारतीय उत्पादकों द्वारा आईएसएमए के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की मांग करते हुए नियमावली के नियम 5 के तहत दायर किए गए एक आवेदन के संबंध में दिनांक 19 दिसम्बर 2017 को मूल जांच शुरु की गई थी। तत्कालीन महानिदेशक (रक्षोपाय) ने दिनांक 5 जनवरी 2018 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जिसमें एक अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। तथापि, कोई भी अनंतिम शुल्क नहीं लगाया गया था। व्यापार उपचार महानिदेशक ने दिनांक 16 जुलाई 2018 को अन्तिम जांच परिणाम जारी किए जिनके आधार पर दिनांक 30 जुलाई 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2018- सीमाशुल्क(एसजी) के तहत दो वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित दरों पर रक्षोपाय शुल्क लगाया गया था:

क) 30 जुलाई 2018 से 29 जुलाई 2019 तक : यथा मूल्य 25% की दर पर

ख) 30 जुलाई 2019 से 29 जनवरी 2020 तक : यथा मूल्य 20% की दर पर

ग) 30 जनवरी 2020 से 29 जुलाई 2020 तक : यथा मूल्य 15% की दर पर

तथापि, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 बी (I) के परन्तुक के अनुसरण में चीन जन. गण. और मलेशिया को छोड़कर, दिनांक 5 फरवरी 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016- सीमा शुल्क (एन टी) में सूचीबद्ध विकासशील राष्ट्रों से आयातों पर शुल्क लागू नहीं है।

घरेलू उद्योग (डी आई):

4. विस्तृत जांच के बाद घरेलू उद्योग का दायरा दिनांक 16 जुलाई 2018 के मूल जांच परिणामों के पैरा 27 के तहत घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र(डीटीए) यूनिटों/निर्यातोन्मुखी यूनिटों (ईओयू) तक सीमित किया गया था।
5. समीक्षा आवेदन तीन आवेदकों की ओर से दायर किया गया है जिनमें दो यूनिट डीटीए में और एक यूनिट सेज (एसईजैड) में हैं। आवेदकों ने घरेलू उद्योग से एसईजैड को निकालने के संबंध में मूल जांच में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
6. मूल जांच परिणामों के पैरा 27 में दिए गए तर्क का अनुसरण करते हुए महानिदेशक ने घरेलू उद्योग के दायरे को डीटीए यूनिटों तक सीमित रखने पर विचार किया है। अतः मैसर्स जूपिटर सोलर पावर लिमिटेड और मैसर्स जूपिटर सोलर पावर इंटरनेशनल लिमिटेड, जिनके पास भारत में समान और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा मौजूद है, पर अधिनियम की धारा 8 बी के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में विचार किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद(पीयूसी):

7. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार था:

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के टैरिफ शीर्ष 8541 और टैरिफ मद 85414011 के तहत वर्गीकृत “सौरसेल, चाहे वे माड्यूलों अथवा पैनलों में असेम्बल किए गए हों अथवा नहीं”। सौर सैलों को बाजार की भाषा में प्रकाश वोल्टीय सैलों के रूप में भी जाना जाता है। प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के तहत सौर प्रकाश को एटमिक स्तर पर सीधे ही बिजली में परिवर्तित किया जाता है और सौर सेल ऐसे ठोस विद्युत उपकरण होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को प्रकाशवोल्टीय प्रभाव से सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं। प्रयोग के तौर पर सौर सैलों को पैक करके

एक एसेम्बली में कनेक्ट किया जाता है और सौर सेलों की ऐसी असेम्बली को सौर पैनलों अथवा सौर माड्यूलों के रूप में भेजा जाता है। सौर सेलों में विजली का कनेक्शन सीरिज में किया जाता है ताकि अपेक्षित आउटपुट वाट प्राप्त हो सके और/अथवा पैरलल कनेक्शन किया जाता है ताकि अपेक्षित करेन्ट क्षमता प्राप्त हो सके।

8. महानिदेशक ने विचाराधीन उत्पाद को वही माना है जो मूल जांच में था। तथापि, यह नोट किया जाता है कि वित्त विधेयक 2020 की तीसरी अनुसूची के तहत टैरिफ मद 8541 4011 ("सौर सेल, चाहे वे माड्यूलों अथवा पैनलों में असेम्बल किए गए हों अथवा नहीं") को निम्नलिखित टैरिफ मदों में विभाजित करने का प्रस्ताव है:

- 8541-4011 – सौर सेल, असेम्बल न किए गए
- 8541-4012 – सौर सेल, माड्यूलों में असेम्बल अथवा पैनलों में निर्मित किए गए

9. आशा है कि इस प्रकार का संशोधन जांच की अवधि के भीतर शीघ्र प्रभावी होगा। अतः इस समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) अधिनियम के अध्याय 85 के टैरिफ शीर्ष 8541 और टैरिफ मद 85414011 एवं 85414012 के तहत वर्गीकृत "सौरसेल, चाहे वे माड्यूलों अथवा पैनलों में असेम्बल किए गए हों अथवा नहीं" है। तथापि, सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है जैसा कि दिनांक 16 जुलाई 2018 के अन्तिम जांच परिणामों में भी उल्लेख किया गया था।

जांचकी अवधि (पीओआई):

10. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2019 - 30 सितम्बर 2019 तक है। यह अवधि बाजार की स्थितियों और ऐसे कारकों पर विचार करने के लिए काफी लम्बी है, जो रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की जरूरत का पता लगाने के लिए संगत हैं। तथापि, महानिदेशक अपने विवेक से जितना आवश्यक समझें, घरेलू उद्योग के लिए जांच की अवधि के बाद के डाटा पर विचार कर सकते हैं।

सूचना का स्रोत :

11. घरेलू उद्योग ने (2014-15 से 2019-20 (सितम्बर 2019 तक) की अवधि के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), वाणिज्य विभाग से विचाराधीन उत्पाद के लिए प्राप्तसौदा-वार आयात संबंधी आंकड़े प्रदान किए हैं और उन पर विश्लेषण के लिए विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने 2016-17 से 2019-20 (सितम्बर 2019 तक) की अवधि के लिए अपने स्वयं के उत्पादन, बिक्री, इन्वेंट्री आदि के संबंध में डाटा प्रदान किए हैं।

समायोजन योजना:

12. घरेलू उद्योग ने प्रथम दृष्ट्या यह साक्ष्य प्रदान किए हैं कि वे मूल जांच में उनके द्वारा प्रस्तुत की गई समायोजन योजना के अनुसार सकारात्मक समायोजन कर रहे हैं और इस पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच में विचार किया गया है। मूल जांच में प्रस्तुत की गयी समायोजन योजना में अन्य उपायों के साथ साथ कच्ची सामग्री की लागत, कनवर्सन लागत, निर्धारित लागत आदि को कम करने पर विचार किया गया है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है, इस समायोजन योजना के साथ वर्तमान लागतों की तुलना करना यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री की लागत, कनवर्सन लागत, निर्धारित लागत, वित्तपोषण लागत, एसजीए लागत आदि के संबंध में पर्याप्त लागत कटौती हासिल कर ली है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह साक्ष्य मिलता है कि घरेलू उद्योग सकारात्मक समायोजन कर रहा है।

क्षति

13. आवेदन की जांच की गई है और यह पाया गया है कि ऐसे प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं कि (क) रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारत में विचाराधीन उत्पादों के आयातों में वृद्धि का स्तर जारी रहा है; (ख) घरेलू उद्योग

विक्रियों की कम लागत, उत्पादन और विक्रियों में वृद्धि तथा कम हानि के संदर्भ में सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है। (ग) तथापि, आयातों से घरेलू उत्पादकों की कीमतों में कटौती अभी भी जारी रही जिससे वित्तीय हानि जारी रही। इस प्रकार घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति नाजुक रही।

समीक्षा जांच की शुरुआत:

14. भारतीय सौर निर्माताओं के संघ(आईएसएमए) के माध्यम से घरेलू उद्योग से लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने पर कि गंभीर क्षति के साक्ष्य हैं और घरेलू उद्योग सकारात्मक समायोजन कर रहा है, नियमावली के नियम 18 के साथ पठित अधिनियम की धारा 8 बी के अनुसार महानिदेशक एतद्वारा विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क जारी रखने की जरूरत की जांच करने के लिए इस नोटिस के माध्यम से एक समीक्षा शुरू करते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना:

15. बद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, संबद्ध वस्तुओं के साथ संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सारी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें।
16. कोई अन्य पक्षकार जो हितबद्ध पक्षकार के रूप में शामिल होना चाहे, वह उपरोक्त पते पर महानिदेशक को इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस संबंध में अनुरोध कर सकते हैं, और निम्नलिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर, निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तरीके से जांच के संबंध में अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
17. सूचना/अनुरोध इस पते पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

महानिदेशक
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

समय सीमा:

18. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना लिखित में भेजी जाए जो नियमावली के नियम 6 (4)के तहत नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उपरोक्त पते पर महानिदेशक को प्राप्त हो जाना चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियमावली के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने संबंधी नोटिस को महानिदेशक द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी प्राप्त होती है तो महानिदेशक, नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम में दर्ज कर सकते हैं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना:

19. अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को, यदि उसके किसी भी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो दो अलग अलग सेट में उसकी सूचना दायर करनी होगी :
 - i. एक सेट पर गोपनीय चिह्नित करके (शीर्षक, पृष्ठ संख्या, इंडेक्स आदि सहित), और
 - ii. दूसरे सेट पर अगोपनीय चिह्नित करके (शीर्षक, पृष्ठ संख्या, इंडेक्स आदि सहित), और
20. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से चिह्नित किए बिना किया गया कोई भी अनुरोध महानिदेशक द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और महानिदेशक उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य

हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रुपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के 4 (चार) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

21. गोपनीय रुपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/ अथवा अन्य सूचना है, जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
22. अगोपनीय रुपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त जानकारी देने के लिए पर्याप्त व्यौरा होने चाहिए। तथापि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है इसका एक विवरणमहानिदेशक की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।
23. महानिदेशक प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि महानिदेशक संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।
24. किसी सार्थक अगोपनीय रुपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध महानिदेशक द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
25. महानिदेशक संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:

26. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो महानिदेशक उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को जैसा भी वे उचित समझें सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

New Delhi, the 3rd March, 2020

Case No.: (SG) 01/2020

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Review Investigation for continued imposition of Safeguard Duty on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” into India.

1. **F. No.22/1/2020-DGTR.**—An application for review and extension of safeguard duty has been filed under Rule 18 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter also referred as the “Rules”) by (i) M/s Mundra Solar PV Limited, a unit in a Special Economic Zone (“SEZ unit”); (ii) M/s Jupiter Solar Power Limited, a unit in the Domestic Tariff Area (“DTA unit”) and (iii) M/s Jupiter International Limited, a DTA unit, through the Indian Solar Manufacturers Association (ISMA), seeking continued imposition of the Safeguard Duty, imposed on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels”

[hereinafter referred to as “Product Under Consideration” or “PUC”] into India to protect the domestic producers of like and directly competitive articles (to the PUC) from serious injury or threat of serious injury caused by such increased imports.

2. The current application seeks continued imposition of the said duty for a further period of four years, pursuant to the first proviso to sub-section 4 of Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 (hereinafter also referred as the “Act”) read with the first proviso to Rule 16(2) of the Rules.

Background

3. The original investigation was initiated on 19th December 2017 on an application filed under Rule 5 of the Rules by five Indian producers through ISMA seeking imposition of safeguard duty against imports of the PUC. The then Director General (Safeguards) issued preliminary findings on 5th January 2018 recommending levy of a provisional safeguard duty. However, no provisional duty was imposed. The Director General of Trade Remedies issued final findings on 16th July 2018, based on which the safeguard duty was imposed for a period of two years vide Customs Notification No. 1/2018-Cus (SG) dated 30 July 2018 at the rates shown below:

- a) from 30th July 2018 to 29th July 2019: @25% ad valorem
- b) from 30th July 2019 to 29th January 2020: @20% ad valorem
- c) from 30th January 2020 to 29th July 2020: @15% ad valorem

The Duty is, however, not applicable on imports from developing nations, as listed in Notification No.19/2016-custom(NT) dated 5th February,2016, except China PR and Malaysia in terms of proviso to Section 8B (1) of the Act.

Domestic Industry (DI)

4. After a detailed examination, the scope of Domestic Industry (DI) was restricted to Domestic Tariff Area (DTA) units/ Export Oriented Units (EOU) vide Para 27 of the original findings dated 16th July 2018.

5. The review application has been filed by three applicants, which includes two units in the DTA and one unit in SEZ, through ISMA. The Applicants have requested for reconsideration of the original decision of excluding SEZ units from DI.

6. Following the same rationale as cited in Para 27 of the original findings, the Director General has considered the scope of DI restricted to DTA units. Therefore, M/s Jupiter Solar Power Limited and M/s Jupiter International Limited, which account for a major proportion of the total production of the like and directly competitive articles in India, are considered as DI in accordance with Section 8B of the Act.

Product Under Consideration (PUC)

7. The product under consideration in the original investigation was as follows:

“Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” classifiable under Tariff Heading 8541 and Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975. Solar Cells are also known as Photovoltaic Cells in the market parlance. Photovoltaic technology enables direct conversion of sunlight into electricity at the atomic level and Solar Cells are solid state electrical devices that convert sunlight directly into electricity by the photovoltaic effect. For practical use, Solar Cells are packaged and connected into an assembly and such an assembly of Solar Cells is referred to as a Solar Panel or Solar Module. The electrical connections are made to the Solar Cells in series to achieve desired output wattage and / or in parallel to provide a desired current capability.

8. The Director General has considered the PUC as in the original investigation. However, it is noted that the tariff item 8541 4011 (solar cells, whether or not assembled in modules) is proposed to be split, vide the 3rd schedule of *The Finance Bill 2020*, into the following tariff items, namely:

- 8541 4011- Solar Cells, not assembled
- 8541 4012- Solar Cells assembled in modules or made up into panels

9. It is expected that such modification will take effect shortly, within the period of investigation. Therefore, the PUC considered in this review is “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” classifiable under the Tariff Headings 8541 and Tariff items 85414011 & 85414012 of Chapter 85 of the Act. The

Customs tariff classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation as was also mentioned in final findings dated 16th July 2018.

Period of Investigation (POI)

10. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2016- 31st March 2017, 1st April 2017- 31st March 2018, 1st April 2018- 31st March 2019 and 1st April 2019- 30th September 2019. The said period is long enough to take into consideration the market conditions and other factors that are relevant for ascertaining the need for continued imposition of Safeguard Duty. The Director General may, however, at its discretion, consider post-POI data, if and to the extent, considered necessary.

Source of Information

11. The DI has provided transaction-wise import data for the PUC from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Department of Commerce for the period 2014-15 to 2019-20 (upto September 2019) and the same has been taken into consideration for analysis. The DI has provided data in respect of their own production, sales, inventory, etc., for the period 2016-17 to 2019-20 (upto September 2019).

Adjustment Plan

12. The DI presented prima facie evidence that they are positively adjusting in accordance with the adjustment plan as proposed by them in the original investigation and so taken note of by the Director General in its final findings. The adjustment plan presented in the original investigation contemplated steps, inter alia, to reduce raw material cost, conversion costs, fixed costs, etc. The DI claims that a comparison of current costs with the said adjustment plan shows that the DI has achieved significant cost reduction on account of raw material cost, conversion costs, fixed costs, finance costs, SGA costs, etc., thereby, prima facie showing that the DI is adjusting positively.

Injury

13. The application has been examined and it is found that there is a prima facie evidence that (a) imports of PUC in India continued at increased levels despite imposition of safeguard duty; (b) DI is adjusting positively in terms of reduced cost of sales, increased production & sales and lowered losses; (c) however, imports still continue to undercut and suppress the prices of DI leading to lower realization and thereby continued financial losses, thus, rendering DI's financial position as fragile.

Initiation of the Review Investigation

14. On the basis of the written application by the Domestic industry through Indian Solar Manufacturers Association, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry regarding evidence of serious injury and that the domestic industry is adjusting positively, the Director General, hereby, initiates a review investigation, in accordance with Section 8B of the Act, read with Rule 18 of the Rules, for examining the need for continued imposition of safeguard duty on the PUC.

Submission of Information

15. The exporters in the subject countries, their government through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

16. Any other party who wishes to be considered as an interested party may submit a request to this effect to the Director General at the below mentioned address within 15 days from the date of this notification, and may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

17. The information/ submissions may be submitted to:

The Director General
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce

Time Limit

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the

Director General at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Director General or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Director General may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

Submission of information on confidential basis

19. The parties making any submission are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

20. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Director General, and the Director General shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

21. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Director General.

23. The Director General may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Director General.

25. The Director General on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

26. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Director General may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Director General